improving Crop Productivity was launched during the IX Plan with effect form 1994-95.

(b) No, Sir. The honey production has increased from 1.3 metric tonnes in 1953-54 to 5907 tonnes in 1994-95.

(c) During 1996-97, an amount of Rs. 113.38 lakhs was released to various implementing agencies under the Central Sector Scheme of Development of Bee-keeping for improving crop productivity. The outlay for 1997-98 is Rs. 250 lakhs.

(d) and (e) Since this was a new scheme launched with effect from October, 1994, the State Designated Agencies (SDA) were not able to incur expenditure to the desired level. The programme is being monitored periodically by the Bee-keeping Development Board (BDB) which has been set up in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation.

उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों का प्रशिक्षण

1100. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के चमोली तथा पौड़ी जनपदों के बेरोजगार नवयुवकों का पहाड़ों से पलायन रोकने के लिये उन्हें बागवानी में प्रशिक्षित करने तथा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के विकास हेतु कितनी राशि आवंटित की गई, उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बागवानी उत्पादकों के प्रशिक्षण तथा दौरा प्रणाली के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत 50 किसानों के एक समूह द्वारा बागवानी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय महत्व रखने वाले स्थानों का दौरा आयोजित करने के लिये 50,000/- रुपए की दर से सहायता मुहैया की जा रही है। वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान चमोली और पौड़ी जिलों में से प्रत्येक के 50 किसानों के दो समूहों के लिये 1.00 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान एक समूह के लिये 50,000/- रुपए मुहैया किये गये। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सहकारी समितियों, कृषक संघों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को खुम्बी, पुष्प कृषि, फल तथा सब्जी विपणन, परिसंस्करण तथा टिशु कल्चर संबंधी फसल कटाई उपरांत की अनुसंरचनात्मक तथा एकीकृत परियोजनाएं स्थापित करने के लिये 4% के सेवा प्रभार की दर से 100.00 लाख रुपए तक की सीमा की उदार ऋण सहायता भी प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार बागवानी के विभिन्न पहलुओं जैसे नर्सरियों की स्थापना, खुम्बी की खेती, मधुमक्खी पालन आदि में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम भी चला रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि/बागवानी के विकास के लिये आबंटित राशि का वर्षवार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र सं०	योजना का नाम	आबंटित राशि		
		1994-95	1995-96	1996-97
(क)	एन०एच०बी० कार्यक्रम			
1.	बागवानी उत्पादकों के प्रशिक्षण के दौरों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण	1.00	0.50	—
2.	पोषणिक उद्यानों की स्थापना	6.50	4.50	4.50
3.	बागवानी के विकास के लिये व्यावसायिक संगठनों की वित्तीय सहायता का अनुदान	0.20	0.12	—

क्र सं०	योजना का नाम	आबंटित राशि		
		1994-95	1995-96	1996-97
(ख)	**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यक्रम**			
1.	सब्जियों पर ए०आई०सी०आर०पी०	2.61	2.67	2.67
2.	खुम्बी पर ए०आई०सी०आर०पी०	2.57	2.60	2.63
3.	आलू पर ए०आई०सी०आर०पी०	3.15	3.31	3.43
4.	राष्ट्रीय बीज परियोजना	5.36	2.42	2.49
5.	उप-उष्णकटिबंधी परियोजना पर ए०आई०सी०आर०पी०	2.60	2.72	2.74
6.	सेव के स्कैब पर ए०आई०सी०आर०पी० (ए०आई०सी०आर०पी०—अखिल भारतीय समंवित अनुसंधान परियोजना)	1.03	1.07	1.12

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पूरे राज्य में कृषि/बागवानी के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाओं के जरिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को राशि निर्मुक्त की जा रही है। हालांकि, क्षेत्रीय/जिला आधार पर धन का आबंटन नहीं किया गया है।

बागवानी प्रभाग की योजनाएं

1. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
2. औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास
3. खुम्बी का विकास
4. उपण कटिबंधी तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों का विकास
5. मूल एवं कन्द वाली फसलों का विकास
6. मसालों का विकास
7. सब्जियों का विकास
8. पान की बेलों का विकास
9. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग

फसल प्रभाग की योजनाएं

1. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०)—चावल
2. आई०सी०डी०पी०—गेहूं
3. गहन कपास विकास कार्यक्रय
4. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
5. गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास

तिलहनों तथा दालों पर प्रौद्योगिकी मिशन की योजनाएं

1. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

Plant variety and Farmers Rights Protection Authority

1101. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are proposing to constitute a body called 'Plant Variety and Farmers Rights Protection Authority';

(b) if so, what are the objectives of the proposed authority in detail;

(c) whether Government are also considering to set up a National Community Gene Fund with grants from Govern-